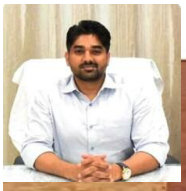

पोल खोल पोस्ट

सच बताना नहीं...दिखाना है...

सिंगरौली से प्रकाशित मासिक समाचार पत्र, आरएनआई नं. MPHIN/2015/69721 नवम्बर 2025, वर्ष: 10 अंक: 11 मूल्य-10 रूपये

मुख्य सचिव बनकर कलेक्टर को दिया फर्जी आदेश, बाप-बेटे समेत तीन ठग गिरफ्तार

कलेक्टर गौरव बैनल की सूझबूझ से बच गया बड़ा फर्जीवाड़ा

सुनील सोनी

पोल खोल पोस्ट, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में प्रशासनिक तंत्र को हिला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने खुद को राज्य का मुख्य सचिव बताकर कलेक्टर को फर्जी आदेश देने की कोशिश की। लेकिन कलेक्टर गौरव बैनल की सूझबूझ और सतर्कता ने एक बड़े फर्जीवाड़े को न सिर्फ नाकाम कर दिया, बल्कि तीन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले में पुलिस ने बाप-बेटे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे गिरोह की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है।

कलेक्टर को आया 'मुख्य सचिव' का फोन

घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ दिन पहले कलेक्टर गौरव बैनल के शासकीय मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल और व्हाट्सऐप संदेश आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन बताया और डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) फंड से संबंधित कार्य तत्काल कराने का दबाव बनाया। शुरुआत में संदेश की भाषा और तरीके से कलेक्टर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से बिना शक जताए बातचीत जारी रखी।

जाल बिछाकर किया खुलासा

कलेक्टर ने तुरंत पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी और योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया गया। सोमवार को आरोपी सचिन्द्र तिवारी और आईबी सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि प्रसाद मिश्रा कलेक्ट्रेट पहुंचे। जैसे ही दोनों कलेक्टर कक्ष में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस फर्जी कॉल की पूरी साजिश वाल्मीकि मिश्रा के बेटे सचिन मिश्रा ने रची थी।अगले दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी सचिन मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। सचिन कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है और अपने पिता की मदद से कलेक्टर को गुमराह कर डीएमएफ फंड से जुड़ा फर्जी काम करवाने की योजना बना रहा था।

बाप-बेटे की साजिश से हड़कंप

जांच में सामने आया कि आईबी के सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि मिश्रा और उनके बेटे सचिन मिश्रा ने मिलकर डीएमएफ फंड के टेंडर कार्यों में दखल देने के उद्देश्य से यह फर्जी कॉल प्लान किया था। इसके लिए उन्होंने वैढ़न निवासी सचिन्द्र तिवारी को भी अपने साथ मिला लिया था, जो कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौदेबाजी की जमीन तैयार करने वाला था।पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 1161/2025 दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

क्या है डीएमएफ फंड

डीएमएफ यानी जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है, जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनता के विकास और पुनर्वास के लिए बनाया जाता है। इसमें खदान संचालकों से मिलने वाली रॉयल्टी का एक हिस्सा जमा किया जाता है, जिसे जिले में विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है।

कलेक्टर की सतर्कता बनी मिसाल

कलेक्टर गौरव बैनल की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में एक मिसाल के रूप में सामने आई है। उन्होंने न केवल एक बड़े फर्जीवाड़े को रोका, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी अब भी जिंदा है।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल और डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। उनसे यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस तरह की ठगी की कोशिश किसी अन्य जिले में तो नहीं की गई।

फर्जीवाड़े की गहराई तक जाएगी जांच

थाना वैढ़न पुलिस ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की धारा 204, 319 और आईटी एक्ट की धारा 66(डी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके।कलेक्टर गौरव बैनल की तत्परता और बुद्धिमत्ता से न केवल सरकारी धन की हानि टली, बल्कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ जिसने पूरे जिले में चर्चा का विषय बना दिया है।

रेवड़ी संस्कृति लोकतंत्र का आधार या प्रलोभन की डगर?

बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनावी रंग में रंग चुकी है। हर चुनावी सभा में, गली-मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं और वादों की बाढ़ आई हुई है। यह चुनावी मौसम पहले की तरह इस बार भी 'रेवड़ी संस्कृति' से सराबोर दिखाई देता है। महागठबंधन हो या एनडीए-दोनों गठबंधन एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ऐसे-ऐसे वादे कर रहे हैं जो सुनने में आकर्षक लगते हैं, पर उनकी व्यवहारिकता और आर्थिक सम्भावना पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। ये चुनावी वादें कैसे पूरे होंगे या जनता के साथ विश्वासघात होगा? हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा रहा है, लेकिन शायद ही किसी ने यह सोचा हो कि इन लोकलुभावन योजनाओं के लिए फंड कहां से आएगा, कैसे उनकी पूर्ति होगी और क्या यह राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति पर और बोझ नहीं बनेगा।

बिहार का यह चुनाव इसलिए खास नहीं है क्योंकि इससे दो दशकों से राज्य का चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य तय होना है-यह खास इसलिये है क्योंकि दोनों गठबंधनों की तरफ से एक जैसी घोषणाएं चल रही है-लोकलुभावन घोषणाओं की। महागठबंधन ने दो दिन पहले 'तेजस्वी - संकल्प' घोषित किया। कांग्रेस, आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों ने बीते दिनों में जो चुनावी वादे किए हैं, उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। दूसरी ओर एनडीए के वादों की लिस्ट भी बेहद लंबी है। शुरुआत में नीतीश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये, 125 यूनिट फ्री बिजली, एक करोड़ नौकरियों का वादा, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, बढ़ी पेंशन-नीतीश ने चुनावी अभियान इस तरह शुरू किया। महागठबंधन ने जवाब में 200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने ढाई हजार, और भी बहुत कुछ देने का वादा किया है। दोनों की गठबंधन की आसमानी घोषणाएं लुभा रही है, जनता को गुमराह कर रही है, सीधे-सीधे रूप में यह वोटों को खरीदने की साजिश है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश की जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 9 प्रतिशत से ज्यादा है, पर जीडीपी में योगदान 2021-22 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गया। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30 प्रतिशत है, जबकि बेरोजगारी ज्यादा है। 2022-23 में राज्य की जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 39.6 प्रतिशत था।

बिहार के सामने सबसे बड़ी समस्या है आय के साधन जुटाने की। कुल कमाई में उसका अपना टैक्स रेवेन्यू केवल 23 प्रतिशत है और केंद्र की तरफ से अनुदान का हिस्सा 21 प्रतिशत। जन सुराज का दावा है कि मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने के लिए 33 हजार करोड़ चाहिए होंगे। इस आंकड़े को सच मान लें तो राज्य के कुल बजट में से रोजमर्रा के कामकाज व योजनाओं का खर्च निकालने के बाद करीब 40 हजार करोड़ रुपये बचते हैं। क्या मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के वादा इससे पूरे होंगे? एनडीए और महागठबंधन, दोनों ही एक-दूसरे की घोषणाओं पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हकीकत में दोनों को बताना चाहिए कि वे किस तरह इन वादों को पूरा करेंगे। बेरोजगारों को भत्ता, महिलाओं को नकद सहायता, युवाओं को लैपटॉप, किसानों के लिए ऋणमाफी-इन घोषणाओं की बाढ़ ने लोकतंत्र को मजबूती देने के बजाय उसे लोकलुभावन जाल में फंसा दिया है। यह स्थिति केवल बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभर रही है, जहां सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता जनता की विवेकशीलता से नहीं, बल्कि प्रलोभनों की मिठास से तय किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, क्योंकि यह मतदाता को उपभोक्ता में बदल देती है और राजनीति को नीति से भटकाकर लाभ की गणित में फंसा देती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई 'रेवड़ी संस्कृति' की अवधारणा आज बिहार की राजनीति में पूर्णरूपेण साकार होती दिख रही है। मुफ्त बिजली, राशन, यात्रा या सहायता योजनाएं अब चुनावी घोषणाओं की अनिवार्य शर्त बन गई हैं। जनकल्याण का उद्देश्य पीछे छूट गया है, सामने है तो केवल वोटों की गिनती। इन घोषणाओं के माध्यम से मतदाता को प्रभावित करना एक तरह का सॉफ्ट करप्शन है, जहां खरीदी खुलकर नहीं होती, पर मानसिक रूप से मतदाता को बंधक बना लिया जाता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की आत्मा पर आघात है, क्योंकि यह नीतियों और सिद्धांतों को कमजोर करती है और राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का खेल बना देती है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब चुनाव नैतिक और नीति-सम्मत हों। चुनाव का अर्थ केवल जीत और हार नहीं, बल्कि समाज के चरित्र और दिशा का निर्धारण है। नैतिक राजनीति वही है जिसमें जनहित को सर्वोपरि माना जाए, न कि तत्कालिक लाभ को। यदि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में केवल आकर्षक वादे ही भरते जाएं और उनके पीछे कोई आर्थिक या सामाजिक दृष्टि न हो, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। मतदाता को चाहिए कि वह ऐसी घोषणाओं से प्रभावित न हो, बल्कि यह देखे कि कौन-सी पार्टी या नेता दीर्घकालिक सुधार, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन की बात कर रहा है। लोकतंत्र उपहार नहीं, उत्तरदायित्व है, इसे समझना और निभाना नागरिक का धर्म है।

वोट किसी के द्वारा दी जा रही मुफ्त सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की स्थिरता, सुशासन और सच्चे विकास के लिए दिया जाना चाहिए। मतदाता का विवेक ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर जनता भावनाओं या लालच में निर्णय लेगी, तो राजनीति और शासन दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी तरह दलों को भी आत्मसंयम रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सत्ता की प्राप्ति साधन नहीं, सेवा का अवसर है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि चुनावी घोषणाओं पर एक नियंत्रण तंत्र बने, चुनाव आयोग और नीति आयोग मिलकर इस पर नियम तय करें कि कोई भी दल अपने घोषणापत्र में ऐसे वादे न करे जिनका कोई आर्थिक आधार न हो। मीडिया को भी केवल वादों को प्रचारित करने में नहीं, बल्कि उनकी समीक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जनता के बीच मतदाता शिक्षण अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग यह समझ सकें कि वोट किसी प्रलोभन का प्रत्युत्तर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है।

वैसे तो दोनों ही गठबंधन एक-दूसरे की घोषणाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा-जद(यू) गठबंधन तेजस्वी की छवि को एक गैर जिम्मेदार सपने बेचने वाले नेता के रूप में गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर है कि जब तक वादों को ठोस नीति में नहीं बदला जाएगा, वे केवल भाषणों की सजावट बने रहेंगे। महागठबंधन को चाहिए कि वह अपने घोषणापत्र को भावनात्मक अपील की बजाय आर्थिक व्यवहार्यता के साथ तैयार करे। यही रणनीति जनता में भरोसा जगाएगी और विपक्ष के हमलों को कमजोर करेगी। तेजस्वी यादव का करिश्मा, संवाद शैली और युवाओं से जुड़ाव उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनाते हैं लेकिन उनकी पूरी चुनावी रणनीति धुआंधार वादों के इर्द-गिर्द घूम रही है। राजनीति में कोई भी वादा तब ताकत बनता है जब उसमें विश्वसनीयता, यथार्थता और क्रियान्वयन की संभावना हो।लोकतंत्र की पवित्रता तभी बचेगी जब राजनीति नीति से संचालित होगी, जब सत्ता सेवा का माध्यम बनेगी और जब मतदाता अपने विवेक से निर्णय लेगा। बिहार जैसे प्रबुद्ध राज्य को चाहिए कि वह रेवड़ी संस्कृति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार, शिक्षा, नैतिकता और सुशासन पर आधारित राजनीति का चयन करे। तभी लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थ में जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकेंगी-हमने वोट से अपना भविष्य खरीदा नहीं, बनाया है।

डायबिटीज की दवाएं दिमागी सेहत को बनाएगी बेहतर

नईदिल्ली। डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दो दवाएं दिमागी सेहत को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती हैं। यह दावा किया है अमेरिका की वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च में। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दवाएं डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारियों के असर को कम करने की क्षमता रखती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खोज अल्जाइमर्स के उपचार में एक बड़ी उम्मीद की तरह है। रिसर्च टीम ने इन दवाओं के प्रभाव को समझने के लिए 55 से 85 साल की उम्र के 47 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया। इनमें से कुछ लोगों को डायबिटीज की दवा एम्पाग्लिफ्लोजिन दी गई, जबकि अन्य को इंसुलिन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कराया गया। नतीजों में पाया गया कि दोनों दवाओं का असर अल्जाइमर्स से पीड़ित मरीजों पर सकारात्मक रहा। एम्पाग्लिफ्लोजिन के प्रयोग से कई प्रतिभागियों के ब्रेन इंजरी मार्कर्स कम हो गए और दिमाग में रक्त प्रवाह (ब्लड फ्लो) में सुधार देखा गया।

वहीं, इंसुलिन नेजल स्प्रे लेने वाले मरीजों में न्यूरोवैस्कुलर हेल्थ और इम्यून फंक्शन में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ। अध्ययन में यह भी सामने आया कि एम्पाग्लिफ्लोजिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मौजूद टाउ प्रोटीन लेवल को कम करने में मदद करती है। टाउ प्रोटीन अल्जाइमर्स की प्रमुख वजहों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा, इंसुलिन स्प्रे लेने वाले लोगों में मेमोरी स्कोर बेहतर हुए और उनके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। हालांकि, यह रिसर्च फिलहाल सीमित पैमाने पर की गई है और इसमें प्रतिभागियों की संख्या कम थी।

जानलेवा प्रदूषण, सरकारों की शर्मनाक नाकामी

भारत की वायु में जहर घुल चुका है। हाल ही में चिकित्सा जनरल में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह निष्कर्ष दिया है कि 2010 की तुलना में 2022 में हवा में जानलेवा साबित होने वाले पीएम 2.5 कणों की मात्रा 38 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इस वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि भारत में सत्रह लाख से अधिक लोगों की अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि मानवता की उस सांस का हिसाब है जो हमारे शहरों, गांवों और जीवन से हर दिन छीनी जा रही है। प्रदूषण अब केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं रह गया है, यह हमारे विकास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के ढांचे पर गहरी चोट कर रहा है। यह भी सहज ही समझा जा सकता है कि 2022 की तुलना में अब वायु प्रदूषण ने और गंभीर रूप लेते हुए जानलेवा हो गया है, क्योंकि बीते तीन वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय किए ही नहीं गए। इसका प्रमाण यह है कि इन दिनों दिल्ली समेत देश के अनेक शहर बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में हैं। यह न केवल सरकार की शर्मनाक नाकामी है बल्कि भयावह और बेहद दर्दनाक भी है।'द लेंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ ऐंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट केवल तथ्य नहीं, एक गंभीर चेतावनी है। लैंसेट की रिपोर्ट ही नहीं, अलग-अलग वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययनों ने भी कुछ इसी तरह के चिन्ताजनक आंकड़े पेश किए हैं। भारत की विशाल आबादी के कारण भी यह संख्या बड़ी हो सकती है, मगर यह समस्या गंभीर चिंतन और तत्काल निवारक कदम उठाए जाने की मांग करती है। भारत में प्रदूषण केवल औद्योगिक उत्पादन या वाहनों की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली, असंतुलित शहरीकरण और अनियोजित निर्माण से भी बढ़ रहा है। हर शहर में धूल, धुआं और अव्यवस्था की परतें जमी हैं। निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल, खेतों में पराली जलाने की आदत, घरेलू ईंधनों का अंधाधुंध उपयोग और बढ़ते वाहनों की भीड़-ये सब मिलकर वातावरण को घुटनभरा एवं जानलेवा बना रहे हैं। हमारे शहर अब सांसों के शत्रु बन गए हैं। बढ़ते प्रदूषण की पीड़ा नीति-निर्धारकों से नहीं, उन लोगों से पूछिए, जो खांसते-खांसते बेदम हो जाते हैं और आखिरकार कई के फेफड़े-हृदय उनका साथ देना बंद कर देते हैं। विडंबना यह है कि इनमें से ज्यादातर उस गलती की सजा भुगतने को अभिशप्त हैं, जो उन्होंने नहीं की।वायु में मौजूद सूक्ष्म कण अब हर सांस में जहर बनकर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता है। कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों ने न केवल हवा को जहरीला बनाया है बल्कि हमारे अस्तित्व की नींव को भी कमजोर कर दिया है। इन स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन के कारण लाखों लोग असमय काल के ग्रास बन रहे हैं, लेकिन ऊर्जा नीति में सुधार की गति अत्यंत धीमी है। सरकारें बार-बार स्वच्छ ऊर्जा की बात करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, लक्ष्य घोषित करती हैं, पर उनका क्रियान्वयन न के बराबर होता है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इस प्रदूषण के शिकार सबसे अधिक वे लोग हैं जो इसके निर्माता नहीं हैं। गरीब मजदूर, झुग्गियों में रहने वाले, बच्चे और बुजुर्ग-ये सभी उस वायु के दंश झेल रहे हैं जिसका लाभ अमीरों ने उठाया है। एक ताजा अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, अमीर तबके का प्रदूषण में योगदान अत्यधिक है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की 'जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025' बताती है कि विश्व के सबसे धनी लोग अपनी संपत्ति और निवेशों के माध्यम से जलवायु संकट को बढ़ा रहे हैं। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 41 प्रतिशत के लिए निजी पूंजी जिम्मेदार है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रदूषण का असली निर्माता संपन्न वर्ग है, जबकि उसकी कीमत गरीब वर्ग अपनी सांसों और जीवन से चुका रहा है। यह असमानता केवल आय की नहीं, बल्कि पर्यावरणीय न्याय की भी है। अमीरों के पास बड़े वाहन हैं, विशाल भवन हैं, आलीशान जीवनशैली है, और वे जीवाश्म ईंधनों पर आधारित उद्योगों में निवेश करते हैं। दूसरी ओर, गरीबों के पास न तो स्वच्छ ऊर्जा है, न शुद्ध हवा। जो अमीर लोग निजी विमानों और विलासितापूर्ण संसाधनों का उपयोग करते हैं, वे एक सामान्य नागरिक की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। यह असंतुलन हमारे समाज को विषमता और अन्याय की ओर धकेल रहा है।

सरकारों की नीतिगत विफलता इस त्रासदी का दूसरा बड़ा कारण है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योजनाएं तो बनती हैं, पर उनमें न तो स्थायित्व होता है, न गंभीरता। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, निगरानी तंत्र कमजोर है, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई नगण्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी का बंटवारा अस्पष्ट है। हर साल सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों की हवा जहरीली हो जाती है, तब कुछ दिन के लिए 'आपात कदम' उठाए जाते हैं, पर जैसे ही धुंध छंटती है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। नीतियों में पारदर्शिता का अभाव और उद्योगपतियों का दबाव भी एक गहरी समस्या है। कोयला आधारित उद्योगों, पेट्रोलियम कंपनियों और निर्माण व्यवसाय से जुड़ी लॉबी सरकारों पर ऐसा प्रभाव बनाए रखती हैं कि कठोर कदम उठाना राजनीतिक दृष्टि से असुविधाजनक बन जाता है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को हमेशा 'महंगा विकल्प' बताकर टाला जाता है, जबकि वास्तव में यह निवेश मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा में है।वायु प्रदूषण का संकट केवल वातावरण में धूल और धुएं का मामला नहीं है, यह आर्थिक अन्याय, राजनीतिक असंवेदनशीलता और सामाजिक उदासीनता का प्रतीक बन चुका है। जो सरकारें जनजीवन सुधारने का वादा करती हैं, वे हवा की गुणवत्ता सुधारने में विफल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से भारत की अर्थव्यवस्था को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान केवल पैसों में नहीं, बल्कि मानव संसाधन की हानि, स्वास्थ्य पर बोझ और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के रूप में भी दिखाई देता है। अब समय है कि इस संकट को केवल पर्यावरणीय मुद्दा न मानकर एक सामाजिक और नैतिक चुनौती के रूप में देखा जाए। हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार धीरे-धीरे छिनता जा रहा है। अमीरों को अपनी जीवनशैली पर संयम लाना होगा, अपने निवेशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ना होगा, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से दूरी बनानी होगी। सरकारों को सख्त नीति बनानी चाहिए, जो न केवल प्रदूषण फैलाने वालों को दंडित करे बल्कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने वालों को प्रोत्साहन दे।नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब तक जनता स्वयं इस समस्या को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आवाज नहीं उठाएगी, तब तक राजनीतिक इच्छाशक्ति जागृत नहीं होगी। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि प्रदूषण से बचाव केवल मास्क लगाने से नहीं होगा, बल्कि सोच और जीवनशैली बदलने से होगा। वायु प्रदूषण एक सामूहिक अपराध बन गया है जिसमें अपराधी कम और पीड़ित अधिक हैं। अब यह वक्त है जब विकास की परिभाषा में स्वच्छ हवा और सुरक्षित वातावरण को सबसे ऊपर रखा जाए। सरकारें यदि सचमुच राष्ट्र की समृद्धि चाहती हैं, नया भारत-विकसित भारत बनाना चाहती है तो उन्हें सांसों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अमीर तबके को भी यह समझना होगा कि जिस हवा को वे अपने निवेशों से दूषित कर रहे हैं, वह अंततः उन्हीं की अगली पीढ़ियों की सांसों को रोक देगी। आज आवश्यकता है एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना की, जो कहे कि हवा किसी वर्ग की नहीं, समस्त जीवन की संपत्ति है। जब तक यह चेतना जागृत नहीं होती, तब तक हर आंकड़ा, हर रिपोर्ट और हर योजना केवल दस्तावेज बनकर रह जाएगी, और भारत की हवाएं यूं ही जहर बनती रहेंगी। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर किसी किस्म की उदासीनता देश और मानवता के साथ अन्याय होगा।

काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, कई घायल

श्रीकाकुलम-आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार 1 नवम्बर की सुबह श्रद्धालुओं के लिए एक भयावह दिन साबित हुआ, जब काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक मास की एकादशी के अवसर पर दर्शन के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 9 श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मंदिर परिसर में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

दर्शन के दौरान अचानक मची भगदड़

जानकारी के अनुसार, एकादशी पर्व के कारण सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पंक्तियों में खड़े थे। तभी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। धक्का-मुक्की के बीच कुछ लोग गिर पड़े और पीछे से आ रही भीड़ उन्हें रौंदती चली गई। चश्मदीदों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी थी और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था।

प्रशासन ने शुरू किया राहत अभियान

हादसे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है।जिला कलेक्टर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि भीड़ नियंत्रण में आखिर कहां चूक हुई।

मुख्यमंत्री नायडू और केंद्रीय मंत्री लोकेश ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, श्रीकाकुलम जिले के काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए।वहीं, केंद्रीय मंत्री नारा लोकेश ने भी इस त्रासदी को ÷एकादशी के दिन घटित दर्दनाक घटना÷ बताते हुए कहा कि सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं अधिकारियों, जिला मंत्री अत्चन्नायडू और विधायक गौथु सिरीशा से बात कर घायलों की मदद और पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

श्रद्धालुओं में शोक की लहर

हादसे के बाद श्रीकाकुलम समेत पूरे आंध्र प्रदेश में शोक की लहर फैल गई है। मंदिर प्रशासन ने अगले आदेश तक विशेष दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष एकादशी पर यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार भीड़ का अनुमान कम लगाया गया था, जिससे प्रशासनिक लापरवाही ने बड़ी त्रासदी को जन्म दिया।राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और हादसे की विस्तृत जांच कराने की घोषणा की है।फिलहाल, श्रीकाकुलम जिला प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अफरातफरी को रोका जा सके।

भारत की सैन्य रणनीति के नए युग की शुरुआत है ऑपरेशन सिंदूरः कर्नल सोफिया

नई दिल्ली। भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य रणनीति के नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने इसे मल्टी-डोमेन प्रिसीजन वॉरफेयर का जीवंत प्रमाण करार दिया। मानेकशॉ सेंटर में आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग- यंग लीडर्स फोरम में बोलते हुए कर्नल कुरैशी ने याद दिलाया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। यह जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध थी। उन्होंने इसे थल, वायु और नौसेना के संयुक्त प्रयास, तकनीकी श्रेष्ठता और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

कर्नल ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने सैन्य मोर्चे के साथ-साथ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी छेड़ी। अतः युवाओं को डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी और फेक न्यूज, दुष्प्रचार से सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, आप केवल फायरपावर में नहीं, फायरवॉल्स में भी प्रशिक्षित हैं। आज युद्ध गोलियों से नहीं, बाइट्स और बैंडविड्थ से लड़ा जाता है।कर्नल ने जोर दिया कि भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है यह युवा ऊर्जा देश की सबसे बड़ी सामरिक संपदा है। भारतीय सेना एआई, साइबर टेक्नोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। आईआईटी, डीआरडीओ और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी चल रही है। चाहे सेना हो या शिक्षा, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, प्रयास, नवाचार और संकल्प ही सफलता दिलाते हैं। कर्नल कुरैशी की प्रेरक वाणी ने आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति और रक्षा क्षेत्र में युवाओं की

निर्णायक भूमिका पर नई रोशनी डाली।ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंक के खिलाफ दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई, बल्कि डिजिटल युग के युद्ध में भारत की तैयारी को भी विश्व पटल पर स्थापित किया। यह संदेश स्पष्ट है भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने याद दिलाया कि 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में उठाया गया।कर्नल के अनुसार, यह कार्रवाई तीनों सेनाओं की तालमेल, तकनीकी तैयारी और आत्मनिर्भर सैन्य क्षमताओं का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कर्नल कुरैशी ने कहा कि भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम है और यह युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है। उन्होंने कहा–आप केवल फायरपावर में नहीं, फायरवॉल्स में भी प्रशिक्षित हैं। आज युद्ध गोलियों से ही नहीं, बाइट्स और बैंडविड्थ से भी लड़ा जाता है।

यूएन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, पीओके में मानवाधिकारों के गंभीर हनन को रोकने की उठाई मांग

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मांग की है कि पाकिस्तान गंभीर मानवाधिकारों के हनन को बंद करे। भारत ने कहा कि पीओके में पाकिस्तान की सेनाएं लोगों के खुले विद्रोह को दबा रही हैं। बता दें, वियतनामी समकक्ष के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की यह बैठक 19वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) से इतर और 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) से पहले हुई। दोनों के बीच हुई इस बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, ÷कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री फान वान गियांग से मिलकर खुशी हुई। दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।इससे पहले शुक्रवार को, उन्होंने कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण भी हो रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना और एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है।राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने 10

वर्षीय अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में एक नए युग की शुरुआत हुई।बैठक के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमने 10 वर्षीय अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। यह हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा।पोस्ट में आगे कहा गया, यह रक्षा रूपरेखा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। यह हमारे बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत है और साझेदारी के एक नए दशक की शुरुआत करेगा।बता दें, राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी एन रेड्डी ने सुबांग एयरबेस पर सिंह का स्वागत किया।

बिहार के लोग दुनिया भर में आगे हैं, लेकिन यहां पिछड़े हैंः राहुल गांधी

बेगूसराय। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में एक बार फिर उतरे। इस दौरान उन्होंने बिहार के बेगूसराय में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दुनिया भर में आगे हैं लेकिन यहां पिछड़े हुए हैं। यहां की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें। वे यहां के लोगों की मदद नहीं करते। वे चाहते हैं कि यहां के लोग मजदूरी करते रहें। उन्होंने कहा कि दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों ने बनाया है, लेकिन वे यहां कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो यहां बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। हम ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहां दुनिया के लोग पढ़ने आएंगे। यहां के लोग दुनिया में मेहनत कर उसे बनाते हैं।

उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए आगे कहा कि यहां जो महागठबंधन की सरकार बनने वाली है वह हर धर्म, हर जाति की सरकार होगी। इसमें हर वर्ग के लिए जगह होगी और सभी का सम्मान होगा।उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने अतिपिछड़ा वर्ग के लिए एक स्पेशल मेनिफेस्टो बनाया है, जिसे हम लागू करेंगे। हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता छोटे व्यापारी होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर गलत जीएसटी लागू करने और नोटबंदी करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इससे छोटा व्यापार बंद हो गया। हमारी सोच है कि यहां छोटे-छोटे व्यापार शुरू हों और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ने महागठबंधन के वोटरों को काटकर बाहर निकाला है। उन्होंने लोगों से वोट चोरी रोकने की भी अपील करते हुए कहा कि ये लोग बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि चुनाव आते हैं और जाते हैं। इस चुनाव में कोई जीते, कोई हारे, लेकिन वे बिहार के लोगों की मदद के लिए आते रहेंगे। यहां के लोग जब भी आवाज देंगे, वे उनके बीच आ जाएंगे।

अधीक्षक पर मेहरबान साहब, एक और छात्रावास का दिया प्रभार

शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास सीधी का हाल,पूर्व से ही छात्रों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं

राजू गुप्ता

सीधी। जिले में संचालित आदिवासी छात्रावासों का प्रभार देने में भी लगातार मनमानी बनी हुई है। हालात यह है कि जिन अधीक्षकों के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं उनको हटाने की बजाय अन्य छात्रावास का भी प्रभार सौंपे जाने में कोई गुरेज नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही मामला शहर में संचालित शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास क्रमांक 2 का सामने आया है। यहां के अधीक्षक डीडी सिंह के विरुद्ध लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। फिर भी इन्हें हटाने की बजाय दूसरे छात्रावास का भी प्रभार सौंप दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग सीधी के सहायक आयुक्त द्वारा आदेश क्रमांक/2641, दिनांक 13 अक्टूबर 2025 में कहा गया है कि छात्रावास का संचालन कार्य प्रभावित न होने के दृष्टिगत शासकीय आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास सीधी क्रमांक 2 के अधीक्षक डीडी सिंह को उसी परिसर में स्थित शासकीय आदिवासी जूनियर बालक छात्रावास सीधी (सामान्य) पुरानी सीधी का प्रभार भी आगामी व्यवस्था तक के लिए सौंपा जाता है। यह जानकारी सामने आते ही विभागीय हल्कों में तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास सीधी क्रमांक 2 के बगल में संचालित आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सामान्य में पदस्थ अधीक्षक रामरक्षा पनिका का स्थानांतरण सिंगरौली जिले के लिए होने के बाद से ही अधीक्षक का पद रिक्त था। उसके प्रभार के लिए अधीक्षक डीडी सिंह द्वारा तरह-तरह के दबाव बनाए जा रहे थे। जिससे उन्हें दूसरे छात्रावास का प्रभार भी मिल सके। दरअसल जिले में आदिवासी छात्रों के लिए तैयार किए छात्रावासों की स्थिति काफी बदहाल है। छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शहर में संचालित शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास क्रमांक 2 के रहवासी छात्रों को मेन्यू के हिसाब से भोजन भी नहीं दिया जाता है। इतना ही नहीं सुबह नाश्ते में छात्रों की कुछ भी नहीं दिया जाता है। छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में विभिन्न प्रकार समस्या हैं जिसके चलते छात्र यहां नहीं रुकते हैं। इन सबको लेकर वो कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए।

उल्लेखनीय है कि सीधी शहर पर स्थिति 85 सीटर शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास में करीब 30 छात्र वर्तमान समय पर रह रहे हैं। छात्रों ने बताया की हॉस्टल में समय से खाना भी नहीं मिलता है जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ किया जाता है। हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि हॉस्टल अधीक्षक डीडी सिंह की मनमानी के चलते उनकी पढ़ाई भी बाधित होती है। शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास क्रमांक 2 के अधीक्षक डीडी सिंह पर यह कोई पहली बार आरोप नहीं लगे हैं इसके पहले यह जिन छात्रावासों की कमान संभाल चुके हैं। सभी जगह छात्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता रहा है।

बजट पूरा, छात्र आधे से भी कम

शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास क्रमांक 2 में विभाग द्वारा 85 छात्रों के रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है लेकिन स्थिति यह है कि यहां 85 सीटर में अधिकतम 25 से 30 छात्र ही रह रहे हैं। उधर जानकारों की मानें तो रजिस्टर में यह संख्या पूर्ण दर्शाकर अधीक्षक डीडी सिंह द्वारा प्रत्येक माह 85 छात्रों के दर से राशि निकाली जा रही है। खास बात यह है कि 85 छात्रों के हिसाब से प्रत्येक माह मिलने वाली सुविधा शुल्क से छात्रावास में रहने वाले 25 से 30 छात्रों को भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। छात्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस संबंध में हम लोगों द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती और जब शिकायत की जानकारी अधीक्षक को मिलती हैं तो वह दुर्व्यवहार भी करते हैं। इस तरह की शिकायतें चालू शैक्षणिक सत्र में आरंभ से ही सामने आ रही हैं। जिस पर भी कोई कार्रवाई न होने से तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

इनका कहना है।

आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सामान्य के अधीक्षक का स्थानांतरण हो जाने से तात्कालिक व्यवस्था में शासकीय आदिवासी जूनियर छात्रावास सीधी क्रमांक 2 के अधीक्षक डीडी सिंह को प्रभार सौंपा गया था। अब नए अधीक्षक की पदस्थापना की जा रही है।

जोधा सिंह उइके, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सीधी।

सोशल मीडिया में छाया रहा सिविल सर्जन पर कालिख पोतने का मामला

जमानत न मिलने से मायूस दिखे विवेक समर्थक,आर्थिक मदद करने वालों की लगी झड़ी, युवा सबसे आगे

पोल खोल पोस्ट,सीधी। सोमवार को जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिविल सर्जन डॉ एस बी खरे के चेहरे पर कालिख पोतने का मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन आज मंगलवार को जब शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय सहित इस घटना में शामिल लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई तो उनके समर्थकों में मायूसी भी देखने को मिली है।

बता दें कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे ड्यूटी समय पर सिविल सर्जन डॉ एस बी खरे अपने निजी नर्सिंग होम में ड्यूटी दे रहे थे जैसे ही इसकी जानकारी शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय के साथ आधा दर्जन लोग केएमएच पहुंच गए और जैसे ही नर्सिंग होम से बाहर निकले उन्हें रोककर उनके ऊपर बोतल में रखा मोबी ऑयल उड़ेल दिया गया और उनके चेहरे पर पोत दिया गया। जिसकी जानकारी मिलते ही समूचे स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मच गया। उधर सोशल मीडिया में जैसे ही इस घटना की फोटो वीडियो पहुंची लोग अपनी अपनी आईडी से शेयर करने लगे, स्थिति यह रही है कि दो दिनों में यह घटना हजारों लोगों की आईडी से शेयर हो गई। सोशल मीडिया में वायरल इस घटना की तस्वीर पर लोगों के द्वारा तरह-तरह के सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं, घटना की निंदा करने वालों की संख्या कम देखी गई है, कारण कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गत दिनों सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक ने मध्यप्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल के सामने रखा था। हालांकि तब कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी चटखारे लगाए थे लेकिन अब विवेक पाण्डेय द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था न सुधरने के विरोध में जिला चिकित्सालय के मुखिया कहे जाने वाले सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोत दी तो विरोधी दल के नेताओं के भी स्वर बदल गए। कल तक जो अस्पताल व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया में जमकर तर्क कुतर्क कर रहे थे वहीं अब इसे गलत बता रहे हैं।

मायूस दिखे समर्थक -शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय सहित अन्य लोगों के खिलाफ जमोड़ी थाने में दर्ज अपराध एवं गिरफ्तारी उपरांत आज मंगलवार को जिला न्यायालय में जमानत की अर्जी लगाई गई थी लेकिन माननीय न्यायाधीश द्वारा इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जैसे ही यह खबर विवेक पाण्डेय के अधिवक्ता द्वारा दी गई समर्थकों के चेहरे मायूस हो गए। जमानत न मिलने के चलते विवेक पाण्डेय सहित उनके सभी साथियों को जिला जेल भेज दिया गया है।

आर्थिक मदद के लिए उतरे लोग -लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ विवेक पाण्डेय एवं उनके साथियों द्वारा उठाए गए इस कदम को सबसे ज्यादा युवाओं ने सराहा है, हालांकि कुछ लोगों ने इस तरह की घटना को अमानवीय बताते हुए निंदा भी की है। खास बात यह रही है कि सोमवार को इस घटना के बाद शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय सहित उनके साथियों की गिरफ्तारी एवं जेल भेजे जाने की खबर मिलते ही लोगों ने जमानत के लिए अधिवक्ता की तलाश करना शुरू कर दिए, इतना ही नहीं इस कार्य में जो आर्थिक बोझ आने वाला था उसके लिए लोगों ने सहयोग के लिए झड़ी लगा दी। बावजूद इसके आज जमानत न मिलने से समर्थकों में मायूसी के साथ साथ आक्रोश भी देखा गया है।

सिहावल विधायक ने लिया फसल नुकसानी का जायजा,किसानों से चर्चा कर जाना फसलों का हाल

पोल खोल पोस्टसीधी। जिले के विधानसभा क्षेत्र 78 सिहावल अंतर्गत कई गांवों में बे-मौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें लगातार हो रही बारिश से पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसके बाद हालात का जायजा लेने आज शनिवार सुबह करीब 9 बजे सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक अचानक गांवों के दौरे पर पहुंचे। विधायक ने ग्राम लिलवार, दुधमनिया, करकोटा, चितवरिया सहित अन्य गांवों का भ्रमण कर किसानों के खेतों में जाकर नुकसान का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।

भ्रमण के दौरान खेतों में खड़े किसानों से बात करते हुए उन्होंने ढांढस बंधाया कि इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में सरकार और प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद प्रत्येक प्रभावित किसान को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। किसी भी पात्र किसान को राहत राशि से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

विधायक श्री पाठक ने मौके पर उपस्थित राजस्व निरीक्षक व पटवारियों को निर्देशित किया कि सर्वे का कार्य किसानों की उपस्थिति में किया जाए, ताकि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर्वे में किसी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने फोन के माध्यम से एसडीएम प्रिया पाठक, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित पटवारियों को तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्वे कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर प्रभावित किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।विधायक ने बताया कि बीते कुछ दिनों से किसानों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि फसल कटाई से पहले ही बारिश ने खेतों में खड़ी उपज को खराब कर दिया है। उन्होंने कहा मैंने गांव-गांव जाकर देखा कि हालात अत्यंत गंभीर हैं। किसानों की मेहनत की पूरी फसल खेत से घर तक नहीं पहुंच पाई और बारिश ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ऐसे समय में किसानों को आर्थिक सहायता मिलना अति आवश्यक है।

एसडीएम को दिए सर्वे के निर्देश

सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा करने के बाद किसानों की वेदना पर चिंता जताई है। उन्होंने तत्काल सिहावल एसडीएम प्रिया पाठक को फोन पर फसल नुकसानी का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। विधायक श्री पाठक ने एसडीएम से यह भी कहा कि सभी हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक इस कार्य में जुट जाए, तथा फसल नुकसानी का सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व किसानों से जरूर संपर्क करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। विधायक की तत्परता से सिहावल विधानसभा क्षेत्र के किसानों में खुशी देखी गई है।

अवैध होर्डिंग को हटाने में नपा प्रशासन का छूट रहा पसीना

राजनीतिक पहुंच का दम भरते है अवैध होर्डिंग संचालक,टेंडर के बाद भी अवैध होर्डिंग का नहीं बंद हो रहा प्रचलन

पोल खोल पोस्टसीधी। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा होर्डिंग का टेंडर जारी करने के बाद भी अवैध होर्डिंग को नहीं हटाया जा रहा है, टेंडर प्राप्त करने वाले ठेकेदार द्वारा इस संबंध में कई बार नगर प्रशासन को पत्र लिखा गया लेकिन राजनीतिक पकड़ का दम भरने वाले अवैध होर्डिंग संचालको के आगे नगर प्रशासन मूक बना हुआ है। सवाल यह उठता है कि जब नगर प्रशासन के बस में नगर पालिका की कमान नहीं है तो फिर किसके दम पर टेंडर निकाला गया था। और निकाला गया तो अवैध होर्डिंग को हटाया क्यों नहीं जा रहा।

उल्लेखनीय हैं कि अवैध होर्डिंग संचालकों के आगे नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है। इसी वजह से तमाम शिकायतों एवं विरोध के बावजूद अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालात यह है कि अवैध होर्डिंग्स लगाने वाले संचालक अपनी राजनीतिक पहुंच का दंभ भरते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि उनके ऊपर नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जावेगी। ऐसा नजर भी आ रहा है। लगातार विरोधों एवं शिकायतों के बाद नगर पालिका की ओर से अवैध होर्डिंग्स पर न तो कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही हटाई जा रही हैं, और न ही अवैध होर्डिंग्स को रोकने के लिए कोई जहमद उठाने की जरूरत समझी जा रही है। इसी वजह से सीधी शहर की मुख्य सडकें एवं चौराहे अवैध होर्डिंग से पटे हुए हैं। नगर पालिका सीधी के जिन कर्मचारियों के ऊपर अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है वह पूरी तरह से तमाशबीन बने हुए हैं। अवैध होर्डिंग्स को लेकर नगर पालिका परिषद के पार्षदों में भी विरोध के सुर उठ रहे हैं। कई पार्षदों का कहना था कि नियम विरुद्ध शहर में लगाई जा रही अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई न करके जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी यह साबित कर रहे हैं कि उनकी सहमति से ही यह सबकुछ गोरखधंधा चल रहा है। होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर पालिका द्वारा टेंडर की कार्रवाई काफी पहले पूर्ण की गई है। शहर में नियमानुसार होर्डिंग्स लगाने की जिम्मेदारी रीवा के ठेकेदार विभू सूरी को सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में नई व्यवस्था के अनुसार होर्डिंग्स लगाने के लिए कई जगह पोल भी लग चुके है। नई व्यवस्था के तहत होर्डिंग्स लगाने के लिए क्या कार्रवाई चल रही है इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है।

फिल्मों में डेब्यू के लिए तब्बू को करना पडा था 8 साल का इंतजार

मुंबई । बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की अदाकारी का असर इतना गहरा होता है कि चाहे वह किसी भावनात्मक दृश्य में हों या किसी तीव्र एक्शन सीक्वेंस में, दर्शकों की नजरें उनसे हटती नहीं। तब्बू का फिल्मी सफर उतना आसान नहीं था, जितना कि उनके फैंस समझ रहे होंगे। उन्हें अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरे आठ साल तक इंतजार करना पड़ा था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तब्बू ने कैमरे के सामने कदम रखा। उनकी पहली फिल्म 'बाजार' थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया। इसके बाद देव आनंद की फिल्म 'हम नौजवान' में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। अभिनय के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही स्पष्ट था। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहली पहचान तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' से मिली, जिसमें उन्होंने अभिनेता वेंकटेश के साथ अभिनय किया। हालांकि बॉलीवुड में तब्बू का असली डेब्यू फिल्म 'प्रेम' से होना था, जिसकी शूटिंग साल 1987 में शुरू हुई थी। फिल्म में उनके साथ संजय कपूर मुख्य भूमिका में थे। लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे आठ साल लग गए और यह 1995 में थिएटर्स तक पहुंच पाई। लंबे इंतजार और तकनीकी देरी के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, मगर इसने तब्बू के करियर की नींव मज़बूत कर दी। इसी फिल्म के बाद तब्बू को धीरे-धीरे पहचान मिलने लगी।

इसके बाद उन्होंने 'विरासत', 'चांदनी बार', 'हम साथ साथ हैं', 'दृश्यम', और 'दे दे प्यार दे' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। हर फिल्म में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए कभी सरल घरेलू महिला, तो कभी सख्त पुलिस अफसर के रूप में। तब्बू की बहुमुखी प्रतिभा का ही परिणाम है कि उन्हें दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि तब्बू ने कभी अपने पिता का सरनेम या पारिवारिक पहचान का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान खुद अपने दम पर बनाई। उनकी बड़ी बहन फराह नाज भी अभिनेत्री हैं, जबकि प्रसिद्ध एक्ट्रेस शबाना आजमी उनकी बुआ हैं। बावजूद इसके, तब्बू ने हमेशा अपनी अलग राह चुनी और अपने काम से दर्शकों का दिल जीता। आज भी तब्बू का नाम आते ही दर्शकों को मजबूत और भावनात्मक किरदारों की याद आती है।

उन्होंने साबित किया कि सफलता केवल जल्दी मिलने से नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत से हासिल होती है। 10 साल की उम्र में शुरू हुआ उनका सफर और आठ साल की देरी से मिला डेब्यू दोनों ने मिलकर उन्हें बॉलीवुड की सबसे सशक्त अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। मालूम हो कि तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनका असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। जब वे केवल तीन साल की थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया था, और उनकी परवरिश उनकी मां ने अकेले की। मां पेशे से शिक्षिका थीं और उन्होंने तब्बू को अच्छे संस्कारों के साथ पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। तब्बू ने अपनी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद में और उच्च शिक्षा मुंबई में पूरी की।

अभिनेत्री कटरीना ने दिया बेटे को जन्म, स्टार्स और फैंस ने दी बधाईयां

विकी-कैट ने शेयर की पोस्ट लिखा- हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं

मुंबई। कटरीना कैफ और विकी कौशल के फैंस के लिए अच्छी खबर है। कटरीना ने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटे के जन्म के साथ ही कैटरीना और विकी की फैमिली में खुशियों का माहौल है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट कर सबको ये खुशखबरी दी, जिसपर स्टार्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। दोनों ने पोस्ट शेयर कर लिखा- हमारे घर खुशियां आई हैं। हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैंज् नवंबर 2025। कटरीना और विकी।

इस पोस्ट को शेयर कर विकी ने लिखा-'आशीर्वाद'। सब सेलेब्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। करीना ने लिखा- कैटज्वेलकम टू बॉय मम्मा क्लब। तुम्हारे और विकी के लिए बहुत खुश हूं। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा- दोनों के लिए बहुत खुश हूं, बधाई। आयुष्मान खुराना ने लिखा- बेस्ट न्यूजज्दोनों को बधाई।

बता दें 23 सितंबर को विकी और कटरीना ने अनाउंस किया था कि दोनों जल्द माता-पिता बनने वाले हैं। उन्होंने लिखा था कि ये उनकी लाइफ का बेस्ट चैप्टर है। विकी ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में पिता की जर्नी शुरू होने से पहले कहा था कि मैं काफी एक्साइटेड हूं और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक्साइटिंग टाइम है और फिंगर क्रॉसबता दें विकी और कटरीना ने 2021 में शादी की थी। दोनों की जोड़ी फैंस की फेवरेट जोड़ी में से एक है। काफी समय से कटरीना की प्रेग्नेंसी की खबरें आ रही थीं, लेकिन दोनों ने इसे छिपाकर रखा था और सितंबर में फिर सबको गुड न्यूज दी थी।

'फोन भूत' का क्लिप साझा कर जैकी श्रॉफ ने यादें की ताजा

मुंबई । बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'फोन भूत' के तीन साल पूरे होने पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म से जुड़ी यादें ताजा कीं। फिल्म का क्लिप साझा करते हुए जैकी ने कैप्शन में लिखा, फिल्म फोन भूत के रिलीज के तीन साल पूरे हो गए हैं। एक्टर के इस पोस्ट के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में फिल्म के मजेदार पलों को याद करते हुए उन्हें बधाई दी। कहानी दो दोस्तों मेजर (सिद्धांत चतुर्वेदी) और गुल्लू (ईशान खट्टर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें भूतों का खासा शौक होता है। उनके घर की दीवारें और सजावट भूतिया माहौल का अहसास कराती हैं। एक दिन दोनों भूतिया थीम वाली पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन उसी दौरान उन्हें करेंट लग जाता है। इसके बाद उन्हें एक भटकती आत्मा रागिनी (कैटरीना कैफ) दिखाई देती है, जो तांत्रिक आत्माराम (जैकी श्रॉफ) से अपने प्रेमी को बचाने के लिए उनकी मदद चाहती है।

रागिनी दोनों को एक बिजनेस आइडिया देती है और उन्हें फोन भूत हेल्पलाइन शुरू करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि वे लोगों को भूतों से निजात दिला सकें। वह यह वादा भी करती है कि वह उन्हें पैसा और शोहरत दिलाने में मदद करेगी। शुरुआत में सब कुछ मजेदार ढंग से चलता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब दोनों को पता चलता है कि रागिनी असल में आत्माराम से बदला लेने के मकसद से उनके पास आई थी, क्योंकि उसी तांत्रिक ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। जैकी श्रॉफ का किरदार फिल्म में रहस्यमय और डरावना दोनों था, जिसने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। अपने करियर में जैकी अब तक 220 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुके हैं। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी हर शैली में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है।अब अभिनेता अपनी अगली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में दिखाई देंगे, जिसका निर्देशन समीर विद्वांस ने किया है। इस फिल्म में जैकी के साथ नीना गुप्ता, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई है। 'तू मेरी मैं तेरा' 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मालूम हो कि गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म फोन भूत में कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर, जैकी श्रॉफ और शीबा चड्ढा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि 1500 रूपये किये जाने की स्वीकृति

आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रूपये की स्वीकृति

भोपाल-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रूपये में वृद्धि कर 1500 रूपये किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।मार्च 2023 से 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की वृे द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना में 250 रुपये की वृे द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये संभावित व्यय होगा।

आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए सूचकांक में छूट प्रदाय किये जाने एवं आचार्य शंकर संग्रहालय ÷अद्वैत लोक÷ के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संस्कृति विभाग द्वारा ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहूधातु प्रतिमा स्थापित की जायेगी। इसके साथ ही आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय, (अे द्वैत लोक) निर्माण, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान, अद्वैत निलयम आदि निर्माण कार्य किये जायेंगे। ये सभी निर्माण कार्य एमपीटीसी द्वारा किए जायेंगे। इसके लिए जून 2025 में 2195 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। मंत्रि-परिषद ने पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सभी शासकीय भवनों को सौर ऊर्जीकृत किये जाने के उे द्देश्य से प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होना अपेक्षित हैं, जिससे शासकीय संस्थानों को बचत होगी। रेस्को मोड में शासकीय विभागों/ संस्थाओं के भवन पर विकासक इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफटॉप संयंत्र का रख-रखाव ऋश्वस्टिह इकाई द्वारा किया जाएगा। रेस्को परियोजना में ऊर्जा विकास निगम` द्वारा प्रत्येक जिले के समस्त शासकीय भवनों जिनकी विदे् युत् संयोजन की कांट्रेक्ट क्षमता 20 किलोवाट या अधिक है, को सौर ऊर्जीकृत किये जाने के लिए जिलेवार पृथक-पृथक निविदा का प्रावधान था। मंत्रि-परिषद द्वारा पृथक-पृथक के स्थान पर एक ही निविदा संचालित करने की स्वीकृति दी गयी है। 20 किलोवाट कांट्रेक्ट क्षमता से कम के संयत्रों की स्थापना रेस्को व्यवस्था के माध्यम से की जायेगी। वन्य क्षेत्रों एवं ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में कैपेक्स मोड पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना के लिए भी स्वीकृति दी गई।मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार भोपाल में 211 साइट्स पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपुर में 14 साइट्स पर कुल 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 साइट्स पर कुल 1661 किलोवॉट, देवास में 14 साइट्स पर कुल 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 साइट्स पर कुल 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 साइट्स पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 साइट्स पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 साइट्स पर कुल 383 किलोवॉट, खंडवा में 16 साइट्स पर कुल 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 साइट्स पर कुल 364 किलोवॉट, रतलाम में 29 साइट्स पर कुल 1229 किलोवॉट, रीवा में 20 साइट्स पर कुल 535 किलोवॉट, सागर में 35 साइट्स पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 साइट्स पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 साइट्स पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 साइट्स पर 714 किलोवॉट कि क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

मांधाता में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रूपये प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गयी है। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

मध्यप्रदेश ने एविएशन क्षेत्र में पूरे देश में बनाई अग्रणी स्थितिः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

रीवा-दिल्ली विमान सेवा से विंध्य क्षेत्र में खुलेंगे विकास के नए द्वार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने एविएशन क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी स्थिति बनाई है। रीवा-दिल्ली-रीवा विमान सेवा से विंध्य क्षेत्र के विकास के आज से नए द्वार खुल रहे हैं। एक समय जिस क्षेत्र में रेल नहीं मिलती थी, आज वहां से विमान सेवा आरंभ हो रही है। पहले रीवा से दिल्ली जाने में करीब 15 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी बड़ी आसानी से लगभग 2 घंटे में तय होगी। विंध्य वाले भी गर्व से कह सकेंगे कि अब दिल्ली दूर नहीं है। विंध्य क्षेत्र, पूरे देश का प्रमुख औद्योगिक और धार्मिक केंद्र है। खनिज संपदा और उद्योगों से समृद्ध यह क्षेत्र, माँ शारदा धाम मैहर और चित्रकूट की आस्था से भी जुड़ा है। विमान सेवा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, खजुराहो और अमरकंटक से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह विमान सेवा खनिज-उद्योग गतिविधियों, धार्मिक स्थल और नेशनल पार्क सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को रीवा से नई दिल्ली विमान सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

देवतालाब के भोलेनाथ और चित्रकूट के भगवान श्रीराम का स्मरण-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के शुभारंभ में देवतालाब के भोलेनाथ स्वयं-भू महामृत्युंजय शिवजी और चित्रकूट के भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए कहा कि माँ शारदा भवानी की कृपा से विंध्य को यह सौगात मिली है, यह पूरे मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि विंध्य जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़कर प्रदेश की प्रगति को नई उड़ान देने के लिए सभी प्रदेशवासी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले साल ही रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बिजली की गति से काम करते हुए आज रीवा-दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने रीवा को प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से जोड़ने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रदेश में चिकित्सा और पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार जारी-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनता का प्रभावी नेतृत्व होने के बाद भी विंध्य क्षेत्र में लंबे समय तक रेल सुविधाओं का अभाव रहा। यह सर्वविदित है कि सुदृढ़ परिवहन किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। आज शुरू हो रही रीवा-दिल्ली विमान सेवा उसी दिशा में प्रदेश का एक सुदृढ़ कदम है। प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा का चिकित्सा और पर्यटन के लिए विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा जैसी अभिनव पहल ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता में नई मिसाल कायम की है। यह सेवा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए वरदान है।

मध्यप्रदेश विमानन क्षेत्र में तेजी से कर रहा है प्रगति- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जो विमानन क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। राज्य सरकार स्पष्ट विजन के साथ हर 150 किलोमीटर पर एक वाणिज्यिक हवाई अड्डा, हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी और हर 45 किलोमीटर पर हेलीपेड उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। पिछले 2 वर्षों में रीवा, सतना और दतिया 3 नए एयरपोर्ट शुरू हुए। इसके पहले 68 वर्षों में केवल 5 एयरपोर्ट विकसित हुए थे। आज प्रदेश में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टियाँ तथा 220 हेलीपेड मौजूद हैं। जल्द ही उज्जैन और शिवपुरी में 2 नए एयरपोर्ट विकसित होने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 लागू की है।

अलायंस एयर संचालित करेगा रीवा-दिल्ली विमान सेवा- रीवा-दिल्ली हवाई सेवामध्यप्रदेश विमानन नीति-2025 के अंतर्गत ड्व्स्न्न प्रावधानों से वित्त पोषित है। यह हवाई सेवा अलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएगी। रीवा हवाई अड्डे का उद्घाटन वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। यह अब 3ष्ट-द्धस्न्न श्रेणी के हवाई अड्डों में शामिल है, जिससे रात्रिकालीन विमान संचालन भी संभव हो सकेगा। विमानन विभाग ने प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर अलायंस एयर को रीवा-दिल्ली हवाई सेवा के संचालन के लिए लेटर ऑफ अवार्ड सौंपा था। यह नई हवाई सेवा न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्री जनार्दन मिश्रा, श्री गणेश सिंह, श्री राजेश मिश्रा, विधायक श्री गिरीश गौतम, श्री नागेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र प्रजापति, श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, श्री विक्रम सिंह, श्रीमती रीति पाठक, अध्यक्ष नगर निगम रीवा श्री व्यंकटेश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल उपस्थित थीं।

एसआईआर का कार्य गंभीरता और प्राथमिकता के साथ करें

भोपाल -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र श्री संजीव कुमार झा ने सोमवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक निर्वाचन सदन, भोपाल में हुई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि समस्त सुपरवाईजर्स, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारीगण अपने बीएलओ से बात करें और मैपिंग तथा एन्यूमरेशन फार्म का वितरण कार्य सम्पन्न कराएं। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही ना की जाए। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से स्वयं और समस्त बीएलओ फील्ड पर मौजूद रहे। प्रत्येक बीएलओ के कार्य की दिन में 3 बार समीक्षा करें और प्रगति से अवगत कराएं। स्वयं भी फील्ड में रहें और जहां कार्य की प्रगति कम हो, वहां स्वयं जाकर बीएलओ से कार्य कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने एन्यूमरेशन फार्म वितरण की जानकारी प्राप्त कर कहा कि शत प्रतिशत मतदाताओं तक समय पर फार्म पहुंचाना सुनिश्चित करें। काम की गति बढ़ाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा चाही गई जानकारी तत्परता से बीएलओ एप में अपडेट करें। सभी अधिकारी एसआईआर के कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री रामप्रताप सिंह जादौन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव, श्री राजेश यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

गोल्ड मेडल जीतने पर अभय का भव्य स्वागत

सीधी। जिले के ग्राम कुबरी निवासी होनहार छात्र अभय मिश्र ने 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेटलिफ्टिंग अंडर-19 वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के कक्षा 10वीं के छात्र हैं। इंदौर में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। अभय के इस शानदार प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके गृह ग्राम कुबरी पहुंचने से पहले ही बढ़ौरा बस स्टैण्ड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन, परिजन एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। लोगों ने माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिलाकर अभय का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों ने कहा कि अभय मिश्रा ने न सिर्फ अपने विद्यालय बल्कि पूरे सीधी जिले का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर अभय मिश्रा के पिता श्रवण मिश्रा परिवारजनों एवं शुभचिंतकों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं कीं। ग्राम कुबरी सहित आसपास के क्षेत्रों में इस उपलब्धि को लेकर हर्ष का वातावरण है। इस अवसर पर श्रीरमा मिश्रा, अटल मिश्रा, अवध मिश्रा, अंबुज मिश्रा, अतुल मिश्रा, पंकज मिश्रा, अदिति मिश्रा, आरोही मिश्रा, पार्थ मिश्रा, अन्वी मिश्रा, कविता मिश्रा, मालती मिश्रा, संतोष मिश्रा, मंगलेश्वर मिश्रा, गिरीश, मिश्रा, क्रांतिकारी मिश्रा, विष्णु दत्त मिश्रा, सुमित मिश्रा, रजनीश मिश्रा, पंकज मिश्रा, अरविंद तिवारी, अरुण सिंह, शिवम मिश्रा, गौरव तिवारी, अजीत तिवारी, विवेक तिवारी, आदर्श तिवारी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

प्रदेश के 38 उच्च शिक्षण संस्थानों को एनआईआरएफ की प्रक्रिया में शामिल होने प्रशिक्षित करेगा उच्च विभाग

प्रति मंगलवार आनलाइन दिया जाएगा प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा विभाग की पहल

भोपाल। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों एनआईआरएफ से मिलने वाले अंक के लिए आवेदन कर सके, इसके लिए प्रदेश के 38 उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय-महाविद्यालय) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को यह प्रशिक्षण प्रति मंगलवार ऑनलाइन दिया जाएगा, जो पांच सप्ताह तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए बकायदा कार्ययोजना भी तैयार कर ली है। प्रशिक्षण के लिए चयनित महाविद्यालयों को एनआईआरएफ के बारे में विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया जाएगा। साथ ही उसके मापदंड भी बताए जाएंगे। प्रति मंगलवार को होने वाले इस प्रशिक्षण में अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्या है एनआईआरएफ

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर रैंक करने की एक प्रक्रिया है। यह देश भर के संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक पद्धति का उपयोग करता है। साथ ही विभिन्न मापदंडों जैसे शिक्षण, सीखने और संसाधन, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, समावेशिता और सहकर्मी धारणा के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है।

इन गतिविधियों के बारे में दिया जाएगा प्रशिक्षण

- -फैकल्टी मेंबर एवं विद्यार्थियों कोगुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और नवाचार में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- -शैक्षणिक संस्थाओं को औद्योगिक संस्थानों के साथ जोड़ने एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना।
- -प्रकाशन, पेटेंट और वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से अनुसंधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करनासाक्ष्य एवं परिणाम आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना।

फर्जी प्रमोशन लेटर बनवाकर पदोन्नति का प्रयास

नगर निगम सिंगरौली की महिला सब इंजीनियर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बृजेश शुक्ला

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। निगम में पदस्थ सब इंजीनियर शिवानी गर्ग पर फर्जी प्रमोशन आदेश बनवाकर पदोन्नति का लाभ लेने के आरोप में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई नगर निगम कमिश्नर सविता प्रधान की शिकायत पर की गई है।

जानकारी के अनुसार, शिवानी गर्ग ने 21 अगस्त 2025 को एक आदेश नगर निगम में प्रस्तुत किया, जिसमें लिखा था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्होंने इस आदेश के आधार पर कार्यभार दिए जाने की मांग भी की थी। आदेश की भाषा और प्रारूप को देखकर कमिश्नर को संदेह हुआ और उन्होंने 12 सितंबर को भोपाल स्थित नगरीय प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जांच के लिए पत्र भेजा।

जांच रिपोर्ट 4 नवंबर 2025 को प्राप्त हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि शिवानी गर्ग के नाम से कोई पदोन्नति आदेश जारी नहीं हुआ है और प्रस्तुत दस्तावेज पूरी तरह फर्जी है। इसके बाद कमिश्नर ने बैढ़न कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस. परस्ते ने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने में और कौन लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि जब आदेश संदिग्ध पाया गया, तब शिवानी गर्ग को आवास योजना अनुभाग में अटैच किया गया था, लेकिन वह एक महीने की छुट्टी लेकर फरार हो गईं और उनका मोबाइल भी बंद है।

इस मामले के उजागर होने से नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारी इसे गंभीर प्रशासनिक अपराध मानते हुए पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रहे हैं।

ट्रेलर ने स्कूटी को मारी टक्कर, दादी की मौत, नाती घायल

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया घंटों सड़क जाम, बोले- तेज रफ्तार कोयला वाहनों ने बना रखी है मौत की सड़कें

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली। जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़ा खाड़ गांव के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार दादी-नाती को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 65 वर्षीय सुखदेवी शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नाती रमेश शाह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, जब दोनों इलाज के लिए सिंगरौली की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर अनियंत्रित गति से गड़ाखाड़ गांव की सड़क पर दौड़ रहा था। इसी दौरान उसने स्कूटी सवार दादी-नाती को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि स्कूटी कई फीट दूर जाकर गिरी और दोनों सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सुखदेवी शाह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, रमेश शाह की हालत नाजुक बनी हुई है।

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर जताया विरोध

घटना की सूचना फैलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन और परिवहन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला ढोने वाले ट्रेलर और हाइवा वाहनों की रफ्तार मौत बन चुकी है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से लोग दहशत में हैं, लेकिन न तो पुलिस सख्ती करती है, न ही निगम प्रशासन रोकथाम के कदम उठाता है।

ड्राइवर फरार, पुलिस ने जब्त किया वाहन

सूचना पर बधोरा चौकी प्रभारी बी.एल. बंसल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद आरोपी ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कोयला परिवहन मार्गों पर गति सीमा लागू की जाए, मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ट्रक-ट्रेलरों के रूट पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

दादी की मौत से परिवार में मातम

सुखदेवी शाह के निधन से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी शोक का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक प्रशासन सड़क सुरक्षा के ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक ऐसे हादसे थमने वाले नहीं हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे ने एक बार फिर सिंगरौली की खतरनाक सड़कों और बेकाबू परिवहन वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

किराये पर दिए गए पीएम आवास होंगे निरस्त, राशि होगी राजसात

सिंगरौली नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान ने दिए कड़े निर्देश, एक सप्ताह में होगी जांच पूरी

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए ईडब्ल्यूएस आवासों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। नगर निगम सिंगरौली की आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान ने कहा है कि जिन लाभार्थियों ने अपने आवासों को किराये पर दे दिया है या स्वयं आवास में निवास नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य शासन के नियमों और प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे सभी हितग्राहियों का आवंटन रद्द किया जाएगा और जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नगर निगम को कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि गनियारी क्षेत्र में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों को लाभार्थियों ने किराये पर दे दिया है, जबकि कुछ मकान महीनों से बंद पड़े हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त सविता प्रधान ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले हितग्राहियों पर नियमों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग न कर सके।नगर निगम प्रशासन का यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य – हर गरीब को उसका घर – की भावना को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।स्थानीय नागरिकों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ऐसे पात्र गरीब परिवारों को लाभ मिल सकेगा, जिन्हें वास्तव में आवास की जरूरत है।

सिंगरौली में स्पा सेंटरों की भरमार,जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर उठे सवाल

नगरी क्षेत्र में तेजी से खुल रहे स्पा सेंटर, नियमों की अनदेखी कर चल रहा कारोबार

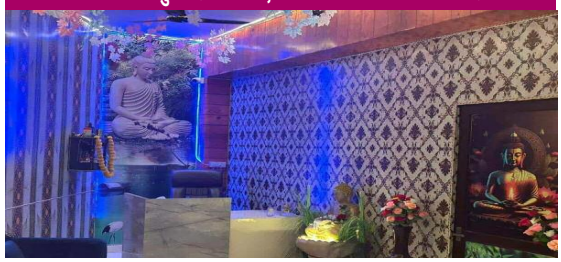

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली। जिले के नगरी क्षेत्र में स्पा सेंटरों की बेतहाशा बढ़ोतरी ने स्थानीय नागरिकों में चिंता का माहौल बना दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में एक के बाद एक स्पा सेंटर खुलते जा रहे हैं, जिनमें से कई बिना आवश्यक अनुमति और मानक नियमों के संचालन में लगे हुए हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्पा सेंटरों में मालिश के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, जिससे क्षेत्र की सामाजिक मर्यादा प्रभावित हो रही है। बावजूद इसके, प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

जानकारी के अनुसार, बीते कुछ महीनों में ही नगरी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों नए स्पा सेंटरों का संचालन शुरू हुआ है, जिनमें न तो सुरक्षा मानकों का पालन होता है और न ही महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर सभी स्पा सेंटरों की जांच की जाए। जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध लाइसेंस नहीं हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सामाजिक वातावरण बना रहे।लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई, तो यह कारोबार बड़े स्तर पर अवैध गतिविधियों का अड्डा बन सकता है। अब देखना यह होगा कि सिंगरौली प्रशासन कब जागता है और इस फैलते नेटवर्क पर अंकुश लगाता है।

एनसीएल मुख्यालय स्तरीय वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता 2025-26 हुई संपन्न

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली- बुधवार को भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में मुख्यालय स्तरीय वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता 2025-26 संपन्न हुई। एनसीएल स्टेडियम, सिंगरौली में आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने 1500 मीटर,100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप,हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर व जैवलिन थ्रो, तीरंदाजी, 3000 मीटर साइकिल रेस, 4*100 मीटर रिले इत्यादि प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया।

प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक मानव संसाधन/ प्रशासन, श्री संजय सिन्हा एवं मुख्यालय स्तरीय जेसीसी मेम्बर्स एवं स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में कुल 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें 64 पुरुष एवं 26 महिलाएं शामिल रहीं। मुख्यालय स्तरीय वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरुष वर्ग से श्री हर्ष शर्मा तथा महिला वर्ग से सुश्री मनीषा छेत्री को चुना गया।

गौरतलब है कि एनसीएल द्वारा प्रतिवर्ष कर्मियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु ऐसी अनेक खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है।

बैढ़न में कबाड़ कारोबार का काला नेटवर्क

आधा दर्जन अवैध दुकानें, पुलिस बनी मूकदर्शक

तेलाई, कचनी, चन्द्रमा टोला, ताली और बलियरी में खुलेआम चल रहा कबाड़ व्यापार, चोरियों का अड्डा बनते जा रहे इलाके

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली-बैढ़न क्षेत्र में अवैध कारोबार की एक और परत खुली है। अब अवैध रेत परिवहन के साथ-साथ कबाड़ व्यापार भी खुलेआम फल-फूल रहा है। कोतवाली क्षेत्र के तेलाई, कचनी, चन्द्रमा टोला, ताली और बलियरी में करीब आधा दर्जन कबाड़ की दुकानें बेखौफ संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इन कबाड़ियों का गोरखधंधा पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इन दुकानों पर चोरी का सामान, लोहे की सरिया, मशीनों के पार्ट्स और वाहनों के पुर्जे तक बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दोपहिया वाहनों की चोरी के कई मामलों में आरोपियों द्वारा बाइक को इन्हीं कबाड़ दुकानों में बेचने की शिकायतें मिलती रहती हैं। फिर भी, पुलिस की जांच हर बार फाइलों में दफन हो जाती है।स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि इन अवैध कबाड़ दुकानों पर वसूलीबाजों का भी बोलबाला है। आए दिन मासिक वसूली के नाम पर कुछ लोग दुकानदारों से पैसे लेते नजर आते हैं। यही वजह है कि ये दुकानें प्रशासन के डर से परे, पूरी सुरक्षा के साथ चल रही हैं।गौरतलब है कि यह वही क्षेत्र है, जहां अवैध रेत परिवहन के ट्रैक्टर रातभर दौड़ते हैं और पुलिस गश्त के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह उठता है कि जब अवैध वाहन सड़कों पर खुलेआम दौड़ सकते हैं और कबाड़ की दुकानें दिन-दहाड़े चोरी का माल खरीद-बेच सकती हैं, तो फिर गश्त और निगरानी का उद्देश्य क्या रह गया है?भवन निर्माण कराने वाले लोग अब अपने लोहे के सामान की रातभर रखवाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि कबाड़ियों के गिरोह रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर सामग्री पार कर देते हैं।कोतवाली क्षेत्र में इन कबाड़ कारोबारियों के विरुद्ध किसी बड़ी कार्रवाई का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालात को देखते हुए शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने आईजी रीवा का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है, ताकि इस अवैध कारोबार और वसूली के गोरखधंधे पर लगाम लग सके। जनता का सवाल अब सीधा है – क्या बैढ़न में पुलिस की निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, या फिर इस खेल में कहीं संरक्षण की परतें छिपी हैं?

कबाड़ चोरों की भेंट चढ़ गये गनियारी प्लाजा के सैकड़ो शटर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

हिमान्शु शर्मा

पोल खोल पोस्ट,सिंगरौली। बैढ़न शहर में अंबेडकर चौक के पास स्थित गनियारी व्यावसायिक प्लाज़ा इन दिनों बड़े पैमाने पर चोरी की घटना का केंद्र बना हुआ है। कोतवाली से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मौजूद इस प्लाज़ा से सैकड़ों लोहे के शटर गायब हो जाना पुलिस की गश्त और निगरानी पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

करीब डेढ़ वर्ष पहले जर्जर हालत के कारण प्रशासन ने व्यापारियों को प्लाज़ा खाली करवाया था। तब से यह भवन बिना सुरक्षा उपायों के खाली पड़ा था, जिसका फायदा कबाड़ माफियाओं ने उठा लिया। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार पिछले तीन से चार महीनों में लगभग 80 फीसदी शटर चोरी हो चुके हैं। आश्चर्य यह कि इतने भारी सामान की ढुलाई के बावजूद पुलिस को कोई जानकारी नहीं हुई।

व्यापारियों का आरोप है कि क्षेत्र में कबाड़ कारोबारियों की सक्रियता बढ़ चुकी है और इन्हें स्थानीय स्तर पर संरक्षण भी मिलता है। निगम प्रशासन को भी प्लाज़ा की स्थिति का पता होने के बावजूद न तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और न ही निगरानी की गई। इस घटना ने शहरवासियों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब कोतवाली के समीप ऐसी चोरी हो सकती है, तो दूरस्थ इलाकों में हालात कितने कमजोर होंगे।

इस मामले में कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने कहा, अब तक किसी ने औपचारिक शिकायत नहीं दी है। आवेदन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने मांग की है कि प्लाज़ा की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि बचा हुआ ढांचा भी चोरी का शिकार न हो।

एनटीपीसी विंध्याचल में मेंटर-मेंटी संबंधों को सशक्त बनाने हेतु रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित

पोलखोल पोस्ट,सिंगरौली- कार्यस्थल से परे संबंधों को मजबूत करने और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनटीपीसी विंध्याचल में 2 नवम्बर 2025 को अंबेडकर स्टेडियम में रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंकुर योजना के तहत मेंटर-मेंटी जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, जिसका सहयोग खेल परिषद ने किया।

प्रतियोगिता ने ऊर्जा, टीम भावना और उत्साह से भरपूर माहौल में मेंटर और मेंटी को एक मंच पर लाया। इस दौरान प्रतिभागियों ने न केवल खेल भावना का प्रदर्शन किया, बल्कि संगठनात्मक एकता और आपसी सहयोग का भी उदाहरण पेश किया।यह प्रतियोगिता केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, बल्कि इसमें अंकुर कार्यक्रम के मूल सिद्धांत – खुला संवाद, पारस्परिक विश्वास, सक्रिय सहभागिता और साझा अनुभवों की भावना झलकती रही।कार्यक्रम का समापन एक सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसकी अध्यक्षता परियोजना प्रमुख संजीब कुमार साहा ने की। इस अवसर पर ए.जे. राजकुमार (महाप्रबंधक - प्रचालन एवं अनुरक्षण), एस.के. सिन्हा (महाप्रबंधक - प्रचालन एवं एफएम), डॉ. बी.के. भराली (महाप्रबंधक - चिकित्सा) और राकेश अरोड़ा (मानव संसाधन प्रमुख) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि एनटीपीसी विंध्याचल अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रगति हेतु भी एक सहयोगी और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऐसे आयोजनों के माध्यम से एनटीपीसी विंध्याचल यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रत्येक नवप्रवेशी को मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और विकास के अवसर मिलें, जिससे संगठन में मेंटरशिप को करियर निर्माण का एक सशक्त माध्यम बनाया जा सके।

जिला खनिज कार्यालय और ऑडिटोरियम टेंडर में गड़बड़ी का खुलासा

7.42 करोड़ के ठेके में सिर्फ एक कंपनी को मिला काम, पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

बृजेश शुक्ला

पोल खोल पोस्ट, सिंगरौली। जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) कार्यालय और ऑडिटोरियम के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 7 करोड़ 42 लाख रुपये के इस भवन निर्माण टेंडर में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरा टेंडर सिर्फ एक ही कंपनी–मेसर्स जीजी इंटरप्राइजेज, इंदौर–को ही मिला, जबकि अन्य फर्मों को तकनीकी कारण बताकर बाहर कर दिया गया।

सिंगल टेंडर को मिली स्वीकृति, बाद में बोर्ड ने किया अस्वीकार

अप्रैल 2024 में जारी इस टेंडर में केवल एक ही ठेकेदार ने भाग लिया था। इसके बावजूद तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन यंत्री मनोज बाथम ने इस सिंगल टेंडर को मंजूरी दे दी। सूत्रों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा दी गई दरें एसओआर से ×.97 प्रतिशत अधिक थीं। बाद में जब यह मामला बोर्ड के संज्ञान में आया, तो बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठे।

आरटीआई पर सीडा ने टाली जानकारी

टेंडर से जुड़ी जानकारी जब आरटीआई के माध्यम से मांगी गई, तो सिंगरौली विकास प्राधिकरण (सीडा) ने सूचना देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस कदम से संदेह और गहरा गया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि टेंडर का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, जिससे एक ही कंपनी को लाभ पहुंचाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भ्रष्टाचार का मामला हैः कांग्रेस

मामले पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि,यह स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। सिंगल टेंडर के बावजूद कार्यादेश जारी कर पसंदीदा ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया। भाजपा सरकार में ऐसी प्रक्रियाएं आम होती जा रही हैं।उन्होंने मांग की कि टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाए।

विशेष परिस्थितियों में हुआ सिंगल टेंडरः सीडा

वहीं, सिंगरौली विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री अरविंद मंडराई ने कहा कि यह टेंडर विशेष परिस्थितियों में जारी किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया, यह टेंडर मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। फाइल देखने के बाद ही वास्तविक स्थिति बताई जा सकेगी।उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में भोपाल में हैं और दस्तावेज़ों का परीक्षण करने के बाद ही जवाब दे पाएंगे।

जांच की आंच बढ़ी, प्रशासन पर दबाव

करोड़ों रुपये के इस विवाद ने जिले के प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। सूत्रों का कहना है कि मामला अब नए कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया है और इसकी विभागीय जांच की संभावना जताई जा रही है।इस पूरे घटनाक्रम ने जिले में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष सफाई में विशेष परिस्थितियों का हवाला दे रहा है, वहीं विपक्ष इसे भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें बता रहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं संपादक सुनील कुमार सोनी एवं प्रकाशक शरद ओझा गायत्री ट्रेडर्स एण्ड प्रिंटर्स जमुआ, जिला-सिंगरौली से मुद्रित एवं प्रकाशित वेबसाइट-www.polkholpost.co.in,
E-Mail-polkhol2015@gmail.com संपादकीय कार्यालय-गुरुद्वारा रोड, क्राइस्ट ज्योति स्कूल के पास, पंजेह बाजार, जिला-सिंगरौली, मध्य प्रदेश, पिन-486889, फोन-07805- 818606 मो.9425178849

समस्त प्रकार के विवाद का न्यायालय क्षेत्र सिंगरौली रहेगा।मासिक पत्रिका पोल खोल पोस्ट में प्रकाशित विज्ञापन, लेख एवं रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के स्वयं के हैं। संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।